

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या- 1178 / V-2-2015-412(आ0) / 2001

देहरादून, दिनांक 21 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में स्थित योजनाएं/परिसम्पत्तियाँ विभिन्न विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र अथवा नगर पालिका क्षेत्रों की सीमा में स्थित है। विकास प्राधिकरण, 'उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973', विनियमित क्षेत्र Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त), तथा नगर पालिकाएं 'उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार गठित एवं शासित होते हैं।

2. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (संशोधित अधिनियम, 2009) की धारा 32 में परिषद अथवा राज्य सरकार द्वारा आवास विकास परिषद के माध्यम से क्रियान्वित/विकसित की जाने वाली आवासीय एवं सुधार योजनाओं को गजट में अधिसूचित किये जाने का प्राविधान है और अधिनियम की धारा 96 के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद की अधिसूचित योजनाओं के संदर्भ में Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्राविधान प्रभावी न होने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में भी यह प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 32 के अधीन अधिसूचित आवास एवं विकास परिषद की योजनाएं उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की परिधि से बाहर होंगी। इस प्रकार, उक्त संदर्भित अधिनियमों के उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं पर विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र एवं नगर पालिका सम्बन्धी उक्त अधिनियमों के प्राविधान लागू नहीं होते हैं और ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के ही प्राविधान लागू होते हैं।

3. यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2009 पारित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के संदर्भ में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद का गठन किया गया है, किन्तु नव गठित उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा उन्हीं योजनाओं/परिसम्पत्तियों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है जो कि उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकसित की जाने वाली योजनाओं के रूप में

अधिनियम की धारा 32 के तहत अधिसूचित की जाये। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में स्थित योजनाएं/परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद को नहीं हो पाया है और प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इन योजनाओं को उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं के रूप में अधिसूचित करना फिलहाल सम्भव नहीं है और बिना ऐसी अधिसूचना जारी हुए इन योजनाओं/परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा स्वतः कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

4. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय आदेश संख्या-2424/ए०पी०यू०-2/यू०के०-04 दिनांक 12-2-2013 एवं पत्रांक-2490/ए०पी०यू०-2/यू०के०-04 दिनांक 21-2-2013 के अनुसार उ०प्र० राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तराखण्ड राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों/योजनाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965" के प्राविधानानुसार मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, उपर्युक्त कारणों से उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद को इन योजनाओं के संदर्भ में स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में, इन योजनाओं/परिसम्पत्तियों के संदर्भ में अग्रिम आदेशों तक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की प्रास्थिति एक सामान्य भूस्वामी/विकासकर्ता की रह जाती है और यथास्थिति उस पर उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973; Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916" (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्राविधान स्वतः लागू/प्रभावी हो जाते हैं।

5. उक्त विधिक स्थिति के आलोक में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की उत्तराखण्ड राज्य में स्थित परिसम्पत्तियों के मानचित्र स्वीकृति के अधिकार के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है -

- (i) जब तक कि प्रश्नगत योजनाएं/परिसम्पत्तियां उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद को हस्तगत नहीं हो जाती ओर उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (संशोधित अधिनियम, 2009) की धारा 32 के तहत उन्हें उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं के रूप में अधिसूचित नहीं कर दिया जाता तब तक इस योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले किसी भी प्रकार के विकास (स्थल विकास/भवन निर्माण) की गतिविधियों तथा भू-उपयोग परिवर्तन आदि के संदर्भ में योजना विशेष की अवस्थिति के अनुसार यथा लागू उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973, Uttar Pradesh (Regulation of Building

Operations) Act, 1958 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के अधीन नियुक्त/नामित उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा (संदर्भित अधिनियमों में निहित अध्यारोही प्रभाव सम्बन्धी प्रावधानों के प्रतिबंधाधीन) संगत अधिनियम में विहित प्रक्रिया अनुसार निर्णय लिये जायेंगे।

- (ii) इस निमित्त उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के स्थानीय अधिकारियों द्वारा सक्षम प्राधिकारियों की अपेक्षानुसार योजनाओं/परसम्पत्तियों के ले-आउट एवं अन्य विवरण सुलभ कराये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-01/2012 उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी।
- (iv) पंजीकृत हो चुकी सम्पत्तियों के ही मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

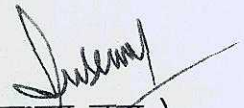

(डी०एस० गर्गल)
सचिव

संख्या-1178/V-2-2015-412(आ०)/2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
2. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उनके कार्यालय आदेश संख्या-2424/ए०पी०यू०-2/यू०के०-04 दिनांक 12-2-2013 एवं पत्रांक 2490/ए०पी०यू०-2/यू०के०-04 दिनांक 21-2-2013 के क्रम में।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
6. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
7. समस्त नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उत्तराखण्ड।
9. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के उत्तराखण्ड राज्य में तैनात समस्त अधिकारीगण/कार्यालय प्रभारी।
10. महानिदेशक, सूचना उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

12. गोपन मंत्रिपरिषद अनुभाग, देहरादून को उनके अर्द्धशा0 पत्र सं0-4/2/VI/XXI/2015-CX दिनांक 03-7-2015 के क्रम में सूचनार्थ।
13. गार्ड फाईल।


(सुभाष चन्द्र)
संयुक्त सचिव